[श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी]

को छः सौ रु. किलो पर सिल्क उपलब्ध कराए। मुझे खेद है कि छः महीने पहले टैक्सटाइल मिनिस्टर साहब ने बनारस में यह एलान किया था कि हम सिल्क इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। हम दिन गिनते गए, हम घड़ियां गिनते गए मगर सिल्क का पता नहीं चला। छः महीने के बाद अब सिल्क आया जब सेठ-साहूकार पूरी तरह से बुनकरों का शोषण कर चुके थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह रेशम जो 715 रु. किलो बिक रहा है, उसका दाम ज्यादा है। मान्यवर, वह छः सौ रू. किलो बिकवाया जाए, चाहे केन्द्र सरकार सबसिडि दे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं इनके विचारों का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Malaviya, you are a senior Member. If you wanted, you could have sought the permission of the Chair. परमिशन तो लेनी ही चाहिए। बिना परमिशन आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बुनकर हैं, बहुत ही समस्याग्रस्त हैं। मैं भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो समस्याएं उन्होंने उठाई उन पर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। लाखों-लाख बुनकर दिल्ली में भी आकर प्रदर्शन कर चुके, बनारस में भी गिरफ्तारियां दीं, जामनगर में भी गिरफ्तारियां दीं। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना होगा जिससे गरीबों की रोटी रोजी चले।

...ought conditions in certain parts of Uttar Pradesh

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर उल्लेख करने का आपने इस माननीय सदन में अवसर दिया।

मान्यवर, गतवर्ष इन शताब्दी का सबसे बड़ा और भयंकर सूखा पड़ा जिसके कारण उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश का अधिकांश भाग बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के नाम पर जो भी धन दिया गया उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। फिर भी किसान ने किसी प्रकार रबी की बोआई की और जब रबी की फसल लगभग तैयार हो गयी उसी समय उत्तर प्रदेश के लगभग दो तिहाई जिलों में उपलवृष्टि और तूफान के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गयीं। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले प्रभावित हुए। बाराबंकी जिले में तो न केवल फसल की बर्बादी हुई बल्कि कई व्यक्ति ओलावृष्टि से मर भी गये। राज्य सरकार ने इस सबंध में जो भी राहत कार्य किया है वह नगण्य और मजाक है। तथा राजस्व व अन्य देय की वसूली किसानों से उत्पीड़नात्मक माध्यम से की जा रही है।

हरियाणा प्रदेश में जहां भी इस प्रकार से किसान देवी आपदा, ओलावृष्टि तूफान और आग लगने से तबाह हुआ है वहां हरियाणा की लोकप्रिय सरकार मुख्य मंत्री माननीय देवी लाल जी ने तुरन्त मौके पर पहुंच कर अथवा अधिकारियों को भेजकर इस प्रकार की आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चार सौ रुपए प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति किया है

अतः लोक महत्व एवं जनहित के इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ओला वृष्टि तथा तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराकर ऐसी आपदा से

पीड़ित किसानों को हर प्रकार की राहत तथा क्षतिपूर्ति की जाये। साथ ही ऐसे क्षेत्रों के किसानों का राजस्व एवं अन्य देयों की वसूली स्थगित कर दी जाये।

Need for more postal telecommunications facilities in Mahbubnagar district of Andhra Pradesh

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice Chairman, Sir, for giving me an opportunity to make my special mention. I hail from the Mahbubnagar district of Andhra Pradesh. I would like to draw the attention of the Communications Ministry to some problems faced by my district, Mahbubnagar. Sir, Mahbubnagar is a vast district with 25 lakhs of population and more than 1500 revenue villages, apart from colonies and hamlets. But it is having only two postal divisions, which are not sufficient for it. That is why I request the hon. Minister of Communications, through you, to take steps to create another postal division in Mahbubnagar district, with headquarters at Nagarkurnool. Apart from that, there are 64 mandal headquarters in the district which are growth centres for which an effective communication system is also required. That is why I request the Minister, through you, to take steps to open sub post offices at all mandal headquarters in the district Already most of the mandal headquarters are having sub offices. I request the Minister to cover the remaining headquarters also with sub post offices.

Coming to telecommunications, unlike the other parts of the country, Mahbubnagar district is not having effective telecommunications, particularly telephones. That is why I request the Minister to take effective steps to increase the efficiency of telecommunications in my district. In this connection, I want to mention that the important towns are Vanaparthy, Nagarkurnool, Gadwal, Shadnagar. They are not having STD provision in the telephones. That is why I request the Hon. Minister, through you, to take effective steps to provide STD facilities in telephones to all these four towns, namely, Vanaparthy, Nagarkurnool, Gadwal and Shadnagar.

Sir, I want to make another request that most of the villages, even major villages are not covered by post offices. There should be provision of post offices in all major villages, and any such major village which does not have a post office should be provided one.

Lastly, Sir, I want to request the Government to provide PCOs and telephones at all the mandal headquarters, if not in all villages. For villages, I do not request at this stage. But I request PCOs at all mandal headquarters in the district. It does not require large allocations as most of the mandal headquarters are already having this facility. Thank you.

Need for remunerative prices to Potato Growers in U.P.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह प्रश्न किसानों से संबंधित है। किसान इस देश की रीढ़ है और इस देश की अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ कृषि जन्य वस्तुओं और उनसे संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश का किसान जितना उत्पादन बढ़ाता है उतना ही मारा भी जाता है। उसी कड़ी में इस साल आलू का उत्पादन 1 लाख 20 हजार टन होने का अनुमान है और उत्तर प्रदेश में करीब पूरे प्रदेश में जितना आलू पैदा होता है उसका 50 फीसदी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और उसका भी 45 प्रतिशत फरुखाबाद इलाहाबाद और उनके अगल-बगल के इलाकों में और मेरठ में भी काफी आलू पैदा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने परेशानी पैदा हो गई है। सरकार ने यह घोषणा की है कि 70 रुपए में नाफेड के द्वारा आलू खरीदा जाएगा,